फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 55 प्रभात जयपुर, शुक्रवार 25 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

How Do You Hide A Disease Nobody Ever Said It Was?

A company that treats honest ignorance like fraud is not protecting itself from a cheat. It is punishing a woman for not being able to see the future

When Dubai almost became a part of India

क्या ज्ञानेश दूसरे धर्मेन्द्र प्रधान साबित होंगे, भाजपा सरकार के लिए

सब तरफ से मांग उठ रही है कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लिया जाए, उन पर महाभियोग चले, खासकर दो चुनाव आयुक्तों द्वारा मीडिया में किए गए खुलासे की वजह से

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 सितम्बर। देशभर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। राहुल गांधी तथा अन्य सभी विपक्षी नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है।

संसद का विशेष सत्र बुलाने, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने और उनके इस्तीफे के बाद, मोदी और शाह के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की मांग की जा रही है। उन्हें राष्ट्रविरोधी और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने तथा 'वोट चोरी' को सुगम बनाने वाले प्रमुख लोगों में से एक बताया गया है।

- नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार को सीईसी के पद से इस्तीफा देकर ''अप्रूवर'' (सरकारी गवाह) बन जाना चाहिए, उनका यह कदम राष्ट्रवादी और देशहित में माना जाएगा।
- राहुल ने कहा कि ''एंटी इन्कम्बैंसी'' भारतीय लोकतंत्र की ताकत है, भारत के बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों को भी एंटी इन्कम्बैंसी का सामना करना पड़ा। पर, क्या कारण है, मोदी की भाजपा सरकार के सामने ''एंटी इन्कम्बैंसी'' नज़र नहीं आती।
- राहुल ने कहा, उन्होंने दो जगहें ऐसी देखी हैं, जहाँ एंटी इन्कम्बैंसी नहीं होती, उनमें से एक देश था सद्दाम हुसैन का इराक व दूसरा है नॉर्थ कोरिया।

राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा: ''वोट भारतीय लोकतंत्र की नींव है। वोट से हमारे संविधान की शक्ति, हमारे कानूनों का अधिकार और हमारे सार्वजनिक संस्थानों की वैधता का जन्म होता है। यह श्रृंखला आधुनिक भारत को परिभाषित करती है।

आज यह श्रृंखला टूट गई है, भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वोट को नष्ट करके इस सरकार और चुनाव आयोग ने हर एक भारतीय की अभिव्यक्ति पर हमला किया है।

राहुल गांधी ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सलाह दी कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर की जा रही 'वोट चोरी' के मामले में सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वे सरकारी गवाह बनते हैं तो यह राष्ट्रवाद का कार्य होगा। उन्होंने मांग की कि ज्ञानेश कुमार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा कि यह 'वोट चोरी' भारतीय राज्य और देश की जनता के खिलाफ किया गया कृत्य है और हम चुप नहीं बैठ सकते; जब यह हो रहा है तो हम चुप रहने से इनकार करते हैं।

उन्होंने कहा, ''मैं कांग्रेस की ओर से भारत की जनता से यह वादा कर रहा हूं कि इस अपराध के लिये मोदी और शाह की जांच की जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस अपराध को बिना सजा के नहीं जाने देंगे।''

राहुल ने दो चुनाव आयुक्तों के रुख की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'वोट चोरी से कानून चोरी और कानून चोरी से संस्था चोरी होती है'

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 सितम्बर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आज देश के शीर्ष चुनाव आयुक्त को देशहित में सरकारी गवाह बनने की सलाह दी और 'वोट चोरी' के अपने पहले के आरोपों को दोहराया।

- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी कर सांसद बने नेताओं द्वारा बनाए गए कानून व संस्थागत परिवर्तन गैर कानूनी हैं।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, ''चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पर अपना नियंत्रण खो दिया है।''

राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ''कानून ज्ञानेश कुमार को संरक्षण देता है। यह प्रधानमंत्री ने किया है।''

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं और कहा, ज्ञानेश कुमार को सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, यह देशहित में होगा।

गांधी ने कहा कि उन्होंने चिंताएं उठाई थीं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, भारत के लोगों ने इस पर विश्वास किया। लेकिन भारत का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हिंद महासागर तक युद्ध फैलेगा, ईरान ने धमकी दी

यह पहली बार है, जब ईरान ने हिंद महासागर का नाम लेकर उसे युद्ध का मैदान बनाने की चेतावनी दी

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 सितम्बर। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर याह्या रहीम सफवी ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका या इज़रायल की ओर से और हमले किए जाते हैं तो तेहरान मध्य पूर्व के संघर्ष को हिंद महासागर तक फैला सकता है। ईरान की समाचार एजेंसी ''फार्स'' द्वारा 24 सितंबर, 2026 को जारी एक वीडियो में सफवी ने कहा, ''चूंकि संघर्ष फारस की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट (ज़लडमरूमध्य) से लाल सागर तक फैल चुका है, इसलिए यह संभव है कि आगे और युद्ध की स्थिति में नए मोर्चे खुलें में और हिंद महासागर तथा शायद उससे भी आगे तक युद्ध फैल जाए।''

- ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार और इस्लामिक रिवोल्यूश्नरी गार्ड कॉर्प के पूर्व कमांडर याह्या रहीम सफवी ने कहा, अगर अमेरिका व इज़रायल ने हमले जारी रखे तो युद्ध हिंद महासागर और उसके आगे तक फैल सकता है। क्योंकि युद्ध पहले ही फारस की खाड़ी और होर्मुज़ स्ट्रेट से आगे बढ़कर लाल सागर तक पहुँच चुका है।
- अगर युद्ध की आग हिंद महासागर तक पहुँची तो इससे भारत को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हिंद महासागर ही भारत के समुद्री व्यापार का केन्द्र है। इससे यूरोप व अफ्रीका के समुद्री मार्ग बाधित हो सकते हैं।

यह पहली बार हुआ है, जब ईरान ने स्पष्ट रूप से हिंद महासागर को संभावित युद्ध क्षेत्र के रूप में नामित किया है। यह बयान तत्काल किसी सैन्य अभियान के आदेश के बजाय, प्रतिरोधक क्षमता और आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी का संकेत देता है। सफवी ने कहा कि ईरानी बलों ने कई संभावित परिस्थितियों के लिए तैयारी की है, जिनमें, सबसे खराब स्थिति में, संघर्ष के बढ़ने की स्थिति भी शामिल है। यह तैयारी अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इरादों को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच की गई है। यह बयान तेहरान की उस रणनीति को रेखांकित करता है, जिसे 'क्षैतिज विस्तार' (हॉरिज़न्टल एस्केलेशन) कहा जाता है, यानी शत्रु के लिए युद्ध की लागत बढ़ाने के लिए संघर्ष का भौगोलिक दायरा बढ़ाना। साथ ही, यह ईरान से करीब 4,000 किलोमीटर दूर स्थित डिएगो गार्सिया में अमेरिकी-ब्रिटिश सैन्य अड्डे की संवेदनशीलता को भी उजागर करता है।

हिंद महासागर में किसी भी तरह का संघर्ष फैलना भारत के लिए गंभीर जोखिम पैदा करेगा। यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश के तेल और गैस आयात का बड़ा हिस्सा होर्मुज़ स्ट्रेट और मध्य पूर्व को एशियाई बाजारों से जोड़ने वाले समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है। संघर्ष के विस्तार से यूरोप और अफ्रीका जाने वाले समुद्री मार्ग बाधित हो सकते हैं, तेल की कीमतों, माल परिवहन की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'खाटूश्याम नगर पालिका चेयरमैन का परिणाम जारी करें'

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव स्थगित करने का आदेश रद्द किया हाईकोर्ट ने

जयपुर, 24 सितंबर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाटूश्यामजी नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए पार्षदों की ओर से डाले गए मतों के आधार पर चुनाव परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने 25 सितंबर को एक पार्षद के प्रस्तावित मतदान पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश वार्ड नंबर 11 से निर्वाचित पार्षद व चेयरमैन पद की प्रत्याशी विनीता पूनिया की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

- हाईकोर्ट ने कहा कि ''डाले गए मतों से जारी करो चेयरमैन पद का परिणाम''।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह ने अदालत को बताया कि खाटूश्यामजी नगरपालिका के बीस वार्ड पार्षदों के लिए गत 9 सितंबर को चुनाव हुए थे और 14 सितंबर को परिणाम घोषित किया गया। इसके बाद चेयरमैन पद के चुनाव के लिए 21 सितंबर को सुबह दस बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि चेयरमैन पद के चुनाव में याचिकाकर्ता सहित दो प्रत्याशी मैदान में थे। तथ्यों के अनुसार तय समय में याचिकाकर्ता सहित 19 पार्षदों ने मतदान कर किया था, केवल वार्ड दस की पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान स्थल पर नहीं पहुंची। याचिका में कहा गया कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतदान का समय बार-बार बढाया और प्रक्रिया को देर रात 11.30 बजे तक खींचा गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह का रोकथाम की कोशिश नहीं की गई थी और ना ही बैलट बॉक्स में छेड़खानी करने की कोई वारदात द र्ज की गई थी, परंतु इसके बाद भी निर्वाचन आयोग ने चुनाव को स्थगित कर 25 तारीख को पुन: आयोजित करने के आदेश जारी कर दिये। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि 22 सितम्बर को ही चुनाव परिणाम जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा था जिसे दरकिनार कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव के दौरान लक्ष्मी देवी के पति ने थाने में उसके अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। इस पर विवाद बढने पर राज्य चुनाव आयोग ने 25 सितंबर का दिन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीजेपी का ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे का अल्टीमेटम

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 सितम्बर। दो चुनाव आयुक्तों द्वारा चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर औपचारिक रूप से आपत्ति जताए जाने की खबर के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता नज़र आ रहा है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने उन्हें इस्तीफा देने या देशव्यापी विरोध का सामना करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इससे विपक्ष की ओर से उनके खिलाफ महाभियोग

- सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके ने कहा कि ज्ञानेश कुमार या तो 48 घंटे में पद छोड़ दें, वरना देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप दंभ भर रहे हैं, शी के साथ उनकी मीटिंग दोनों देशों के रिश्तों को पूर्णतया नया मोड़ देगी

उनका इशारा है कि जैसे बुश-गोर्बाच्येव मीटिंग और निक्सन-माओ त्से तुंग की मीटिंग से विश्व कूटनीति में भारी बदलाव आया था, कुछ वैसा ही शी के साथ उनकी मीटिंग का नतीजा रहेगा

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 सितम्बर। न्यूयॉर्क में चल रही युनाइटेड नेशन्स जनरल असैम्बली (यूएनजीए) डिप्लोमैटिक अहमियत और वैश्विक प्रभाव के मामले में, वॉशिंगटन में हो रहे एक और बड़े और चर्चित इवैंट के सामने फीकी पड़ गई है, जहाँ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप मिल रहे हैं।

हमेशा की तरह, ट्रंप वास्तविक मुद्दों के बजाय शान शौकत में ज्यादा यकीन रखते हैं और शी जिनपिंग का स्वागत भी बेहद भव्य और किसी बड़े शो जैसा था। ट्रंप को रैड कारपेट वाला स्वागत पसंद है। उन्होंने उस एयरबेस पर 100 फीट लंबा रैड कारपेट बिछवाया,

- पर, यह बात सही नहीं है, क्योंकि 9 साल पहले वर्ष 2017 में जब ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, उनकी तुलना में अब चीन का रूतबा और महत्व बढ़ गया है, जबकि ट्रंप का महत्व घटा है, खासकर ईरान व यूक्रेन के मोर्चे पर असफलता के कारण।
- विशेषज्ञों का कहना है कि वे इस मीटिंग में कोई भारी विशेष निर्णय होने की आशा नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप शो मैन शिप में विश्वास रखते हैं और पहेलियों में बात करते हैं। जैसे शी के स्वागत के लिए उन्होंने विशेष रूप से 100 फीट लंबा कारपेट बनवाया और खुद एयर बेस पर शी का स्वागत किया।

जहाँ शी जिनपिंग अमेरिका में उतरे। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप स्वयं एयरबेस पर शी जिनपिंग का स्वागत करने के लिए मौजूद थे, जो सामान्य परंपरा से अलग था।

वर्तमान शी-ट्रंप शिखर वार्ता की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ शी जिनपिंग की पिछली मुलाकात की तुलना में आज चीन कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। दूसरी ओर, डॉनल्ड ट्रंप ईरान युद्ध से लेकर यूरोप में अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के साथ विवादों तक, अपनी लगातार गलतियों के बोझ से दबे हुए हैं। इसके अलावा, वे व्लादिमीर पुतिन पर अपने व्यक्तिगत प्रभाव के बड़े-बड़े दावे भी करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि वे पुतिन को शांति समझौते के लिए तैयार कर सकते हैं।

ट्रंप बढ़ा-चढ़ाकर बातें करने के लिए जाने जाते हैं और वे पहले ही दावा कर चुके हैं कि शी जिनपिंग के साथ उनकी शिखर वार्ता अब तक की सबसे महत्वपूर्ण शिखर वार्ता होगी। हालांकि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नितिन नबीन दादिया व अल्बर्ट हॉल पर कार्यक्रमों में भाग लेंगे

जयपुर, 24 सितम्बर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पं. दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर शुक्रवार को जयपुर में आयोजित होने वाले ''सेवा संकल्प'' समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्य कार्यक्रम दादिया में होगा, जबकि इससे पहले प्रात: 7:30 बजे नितिन नबीन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की।

अल्बर्ट हॉल पर ''स्वच्छता ही सेवा'' कार्यक्रम में भाग लेंगे। जहां आमजन को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी। दोपहर 12 बजे से दादिया में आयोजित सेवा संकल्प समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही, वे दोपहर 2:30 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम में युवा संवाद कार्यक्रम में भी दोनों शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक लेकर इन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की।

'राजस्थान रॉयल्स टैक्स चुकाएगी अथवा नहीं, इसका फैसला जीएसटी ट्रिब्यूनल करे'

हाईकोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल गठित नहीं होने से यह मामला कई वर्षों से लंबित है, इसलिए फैसला आने तक अंतरिम रोक जारी रहेगी

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 24 सितम्बर। आईपीएल क्रिकेट मैच के टिकट बिक्री पर राजस्थान रॉयल्स से स्टेट जीएसटी वसूलने के संबंध में राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी आदेशों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगायी है। अदालत ने कहा कि, यह मामला वर्ष 2018 से लंबित है, चूंकि इस मामले की सुनवाई जीएसटी अपीलीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष होनी चाहिए थी, परंतु इस ट्रिब्यूनल का गठन ही नहीं हुआ था, इसलिए मामला लंबित रहा। अदालत ने कहा कि, इस मामले की सुनवाई एक माह में ट्रिब्यूनल में की जाए और ट्रिब्यूनल के अधिकारी, याचिकाकर्ता कंपनी रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्रा. लि. को उसका पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान करें। यह आदेश न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में राजस्थान रॉयल्स की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका पेश हुए थे।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में फ्रेंचाइजी है, उसकी संचालक कंपनी रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्रा. लि. का कार्यालय मुंबई स्थित हीरानंदानी बिजनेस पार्क में है। ज्ञात रहे कि वर्ष 2016-17 में जब जी.एस.टी. लागू किया गया था, तब केन्द्रीय कर

- अदालत ने कहा कि, इस मामले की सुनवाई एक माह में ट्रिब्यूनल में की जाए और ट्रिब्यूनल के अधिकारी, याचिकाकर्ता कंपनी रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्रा. लि. को उसका पक्ष रखने का पूरा मौका दें।
- ज्ञात रहे कि आईपीएल क्रिकेट मैच के टिकट वितरण को लेकर राजस्थान कर विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान रॉयल्स को प्रदेश में भी कर चुकाने का नोटिस व आदेश जारी किया था।
- जबकि राजस्थान रॉयल्स का कहना है कि, उन्होंने टिकट बेचान का अनुबंध ''बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्रा. लि. से कर रखा है, यह कंपनी हर प्रदेश में टिकट बेचने पर टैक्स पहले से चुका रही है।''

विभाग ने इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्वत: ही मुंबई में किया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में इस फ्रेंचाइजी ने सभी क्रिकेट मैच के टिकट बेचने का अनुबंध ''बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्रा. लि.'' के साथ किया था, जो कि अलग-अलग शहरों में होने वाले आईपीएल मैचों में राजस्थान रॉयल्स के टिकट बेचती थी। यही कंपनी टिकट बेचने पर टैक्स भी भर रही थी।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान रॉयल्स ने जब सभी मैचों के अपने टिकट ''बिग ट्री'' कंपनी को बेच दिए थे, तभी इस लेनदेन से जुड़ा इंट्रीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (आईजीएसटी) भर दिया था, जो कि करोड़ों रुपए का था। राजस्थान रॉयल्स का कहना है कि भले ही यह समझौता मुंबई में हुआ और उस पर टैक्स भी मुंबई में भरा गया, लेकिन इस टैक्स राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा ही केन्द्र सरकार के खाते में जाता है, शेष 50 फीसदी टैक्स गृह राज्य को मिलता है, जहां मैच आयोजित हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान में आयोजित हो रहे मैचों का इनपुट टैक्स राजस्थान सरकार को मिलेगा, ना कि महाराष्ट्र सरकार को।

यहां यह भी गौरतलब है कि, राजस्थान कर विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 2018 में ही राजस्थान रॉयल्स को पहले नोटिस दिया और उसके बाद बिना सुनवाई किए ही यह आदेश पारित कर दिए कि, राजस्थान रॉयल्स की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डॉ. भगवती प्रसाद सारस्वत राजस्थान विश्वविद्यालय के कुल गुरु नियुक्त

जयपुर, 24 सितम्बर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने गुरुवार को आदेश जारी कर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में डॉ. भगवती प्रसाद सारस्वत को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय

- राज्यपाल ने युद्धवीर सिंह को सीकर तथा प्रो. नरसी राम विश्नोई को बीकानेर का कुलगुरु बनाया।

सीकर में डॉ. युद्धवीर सिंह को तथा महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में प्रो. नरसी राम विश्नोई को कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। बागडे ने राज्य सरकार के परामर्श से कुलगुरु पद पर नियुक्तियों के यह आदेश जारी किये हैं। यह नियुक्तियां कुलगुरु के कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए लागू होंगी।